भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1549
(12 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आवासहीन परिवार

1549. डॉ. थोल तिरुमावलवनः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास 01.01.2015 और 31.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों की संख्या का ब्यौरा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय मार्च, 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के आवासों का निर्माण करने के समग्र लक्ष्य सहित ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) कार्यान्वित कर रहा है। कुल 2.95 करोड़ आवासों के लक्ष्य की तुलना में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों के लिए दिनांक 08.12.2023 तक 2.94 करोड़ से अधिक आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं और 2.51 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

एसईसीसी सर्वेक्षण 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

आवासहीन परिवारों के संबंध में लोकसभा में दिनांक 12.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1549 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य का नाम	एसईसीसी सर्वेक्षण 2011 के अनुसार आवासहीन परिवार
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7
आंध्र प्रदेश	11,745
अरुणाचल प्रदेश	3
असम	3,089
बिहार	4,004
दादरा एवं नगर हवेली	82
गोवा	31
गुजरात	4,707
हरियाणा	1,856
हिमाचल प्रदेश	667
जम्मू और कश्मीर	2,169
कर्नाटक	3,714
केरल	1,290
मध्य प्रदेश	23,048
महाराष्ट्र	29,048
मणिपुर	110
मेघालय	123
मिजोरम	9
नागालैंड	26
ओडिशा	5,309
पुदुचेरी	22
पंजाब	1,092
राजस्थान	12,976
सिक्किम	120
तमिलनाडु	2,381
त्रिपुरा	718
उत्तर प्रदेश	10,419
पश्चिम बंगाल	4,193
छत्तीसगढ	7,086
झारखंड	758
उत्तराखंड	981
तेलंगाना	4,304
लद्दाख	1
कुल	**1,36,088**

*****